**सोवियत संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनायें**

2625. श्री राम जेठमलानी :
श्री धीरेन जे० शाह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्षों में भूतपूर्व सोवियत संघ की वित्तीय सहायता से विभिन्न विद्युत परियोजनायें स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य अब भी चल रहा है और उनकी मौजूदा लागत के बारे में क्या आकलन है;

(ग) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद से इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य ठप्प हो गया है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 तक इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और उस पर सरकार प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि अदा कर रही है;

(ङ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं के निर्माण की लागत को पूरा करने के लिये अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से संपर्क किया है ; और

(च) दिसम्बर, 1992 तक किन-किन परियोजनाओं की निर्माण लागत को पूरा करने के लिये सरकार ने व्यवस्था कर ली है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू)** : (क) से (च) भारत में ताप विद्युत परियोजनायें अधिष्ठापित किये जाने के लिये तत्कालीन सोवियत यूनियन के साथ सात समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे । इनमें विन्ध्याचल चरण-1 ताप विद्युत परियोजना, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना, विन्ध्याचल चरण-2, टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स, मैथान ताप विद्युत परियोजना, कायामकुलम ताप विद्युत परियोजना, मंगलौर ताप विद्युत परियोजना और विन्ध्याचल बीना-नागदा पारेषण प्रणाली शामिल है । इनमें से विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-1 पूरी हो गई है और कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना अंतिम चरण में है जबकि टिहरी काम्पलैक्स में कुछ कार्य किया गया है । टिहरी समेत शेष परियोजनाओं के लिये ऋण समझौतों हेतु रूसी परिसंघ के साथ पुनः बातचीत करनी पड़ सकती है । 1977 के बाद जिन परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे इनके लिये ऋण सोवियत यूनियन राज्य से राज्य सहायता के आधार पर उपलब्ध था तथा वार्षिक ब्याज की दर 2.5% थी और इसका भुगतान 20 वर्षों में किया जाना था जिसमें तीन वर्ष की छूट की अवधि भी शामिल थी ।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को भारी घाटा**

2626. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान भी भारी आर्थिक घाटा वहन किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस घाटे की अनुमानित राशि कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में विद्युत पारेषण के दौरान होने वाली हानि का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में अधिक है जबकि क्षेत्रफल के अपेक्षाकृत कम होने के कारण यह अनुपात कम होना चाहिये;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की अनेक

सरकारी और अन्य संस्थाओं पर भारी धनराशि बकाया है, यदि हां, तो यह राशि कितनी है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान प्रशासनिक व्यय में 200 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि विद्युत और कोयले के क्रय मूल्यों में क्रमश: 106 प्रतिशत और 123 प्रतिशत वृद्धि हुई है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू)** : (क) से (ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान डेसू द्वारा 264.42 करोड़ रु० के घाटे का अनुमान लगाया गया है। 1991-92 के दौरान डेसू को अनन्तिम पारेषण एवं वितरण हानियां 22.50% थी जोकि राष्ट्रीय औसत के सन्दर्भ में तुलनीय है। उपर्युक्त हानियों को कम करने हेतु डेसू द्वारा तकनीकी एवं बाध्यकारी दोनों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, डेसू द्वारा विभिन्न सरकारी निकायों एवं अन्य संस्थानों/उपभोक्ताओं से लगभग 869 करोड़ रु० की राशि वसूल की जानी है। वर्ष 1991-92 में, प्रशासनिक व्यय सहित डेसू के राजस्व व्यय में 1989-90 के दौरान व्यय की तुलना में केवल 33% की वृद्धि हुई जोकि निवेश संबंधी लागत और उपभोक्ताओं/प्रचालनात्मक कार्यकलापों की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उचित सीमा में है।

**बिहार में नई विद्युत परियोजनायें**

2627. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में नए विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में बिहार सरकार से प्राप्त कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचारार्थ लंबित हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार कितने प्रस्तावों को कब तक मंजूरी देने का विचार रखती है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू)** : (क) और (ख) बिहार की निम्नलिखित दो परियोजनायें तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के जांचाधीन है :—

| क्र सं० | स्कीम का नाम | क्षमता (मे०वा०) |
|---|---|---|
| 1 | चांडील टी पी० एस० | 2×250 |
| 2 | मुजफ्फरपुर टी० पी० एस० विस्तार | 2×250 |

परिषोजना प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के लिए सभी आवश्यक निवेशों तथा स्वीकृतियों को सुनिश्चित कर दिए जाने के पश्चात् ही इन परियोजनाओं के लिए तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।

**Foreign and Domestic Investment in Power Sector**

2628. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government have received over 40 proposals for investment in power sector both from the foreign and domestic companies;

(b) if so, what are the names of the companies with respect to their investment for respectve capacity;

(c) the total investment that is visualised in these power projects;

(d) the number of projects that have already been granted Government's approval;

(e) what are the reasons for which the other projects have not yet been granted clearance; and

(f) by when the proposals for remaining power projects will be cleared?